

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 21/2022

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोजेन्ट

कानसिंह पुत्र शेतानसिंह जाति पुरोहित निवासी
नारवा खुर्द तहसील खीवसर जिला नागौर

नायब तहसीलदार, खीवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 27.09.2023

{1}-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खीवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 11/2022 सरकार बनाम कानसिंह में निर्णय दिनांक 18.05.22 के तहत मौजा नारवा खुर्द की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.06.22 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 18.05.22 की फोटोप्रति, नायब तहसीलदार खीवसर के प्रकरण संख्या 11/22 के फर्द अहकाम दिनांक 12.04.22 से 11.05.22 तक की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, नकल आवेदन की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)- अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधिविरुद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त योग्य है।


{2}(II)- अपीलान्त के पिता शैतानसिंह ने अपने खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा संख्या 369 वाके मौजा नारवा खुर्द में से दो बिस्वा भूमि का सामुदायिक भवन बनाये जाने हेतु राजहक में सन् 2000 में समर्पण किया था। दो बिस्वा भूमि का समर्पण किया गया उस समय भी स्नानघर और पशुओ के बैठने बांधने का टीनशेड बना हुआ था जो इस समर्पित की गई दो बिस्वा भूमि के बाहर बने हुए थे और इस स्नानघर व पशुओ के लिए बने टीनशेड की भूमि का अपीलान्त के पिता ने राजहक में कभी समर्पण नहीं किया था।

{2}(III)-खसरा नम्बर 369 में से अपीलान्त के पिता ने मात्र दो बिस्वा भूमि का ही समर्पण किया था लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों ने दो बिस्वा की जगह आठ बिस्वा भूमि गलत रूप से गैर मुमकीन भूमि दर्ज कर दी जो बिना क्षेत्राधिकार के दर्ज की गई क्योंकि अपीलान्त के पिता ने 8 बिस्वा भूमि का समर्पण कभी नहीं किया था केवल 2 बिस्वा भूमि का ही समर्पण किया था। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में 369/1 का रकबा 8 बिस्वा (0.647 हैक्टर) भूमि का इन्द्राज गलत दर्ज होने के कारण अपीलान्त को किसी सूरत में अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है।

{2}(IV)-अपीलान्त के पिता द्वारा ही खसरा संख्या 369 में से भूमि समर्पित की गई थी जिसके नये खसरा संख्या 369/1 दर्ज हुए मगर इसमें इसका रकबा 2 बिस्वा के स्थान पर 8 बिस्वा गलत दर्ज किया गया। अपीलान्त के पिता की समर्पित भूमि का फल धारा 91 की कार्यवाही कर अपीलान्त को दिया गया। जिस दो बिस्वा भूमि का समर्पण किया गया उस पर सामुदायिक भवन बना हुआ है।

{2}(V)- पटवारी हल्का ने मौके पर आकर कभी नाप चौप नहीं किया न मौके रिपोर्ट तैयार की। तहसील में बैठ कर ही सारी झूठी रिपोर्ट तैयार की गई।

{2}(VI)-अपीलान्त के विरुद्ध निर्णय करने से पूर्व अपीलान्त को नोटिस नहीं दिया न अपीलान्त पर किसी नोटिस की तामील हुई न सवार नोटिस लेकर अपीलान्त के पास आया और न अपीलान्त ने कभी


अपर कलक्टर, नागौर

नोटिस लेने से इंकार किया। कुछ समय पहले पटवारी ने बताया कि अपीलांट का कब्जा पुलिस मदद से हटाया जायेगा क्योंकि तहसील से फैसला उसके खिलाफ हो गया है तब अपीलांट ने खींवसर आकर पता कराया तब पहली बार अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। उससे पहले अपीलांट को निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। निर्णय की जानकारी होते ही अपील पेश की गई।

{2}(VII)—नकले मिलने पर अपीलांट को जानकारी हुई कि सवार ने नोटिस पर अपीलांट द्वारा नोटिस नहीं लेने की झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांट के पास नोटिस लेकर सवार कभी भी नहीं आया। नोटिस पर किसी भी मौतवर व्यक्तियों कि हस्ताक्षर नहीं है। उक्त नोटिस पर किसी भी सूरत में नहीं मानी जा सकती। नोटिस तामीलसुदा नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः नोटिस जारी करना चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अपीलांट की तामील नहीं होने के कारण अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही भी नहीं की गई और सीधे ही अपीलांट के पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधिविरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

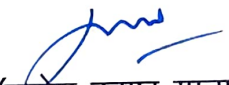
{2}(VIII)—अपीलांट की तामील हुए बिना, अपीलांट से जवाब लिए बगैर तथा अपीलांट को साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IX)—अपीलांट का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। स्नानघर व जानवरों का टीनशेड अपीलांट के भाई प्रतापसिंह के बन्त कब्जे में होते हुए भी अपीलांट के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही गलत की गई है। स्नानघर व टीनशेड भी खातेदारी की भूमि में है मगर फिर भी अपीलाधीन निर्णय गलत पारित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा नारवा खुर्द में स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 11/2022 सरकार बनाम कानसिंह में निर्णय दिनांक 18.05.22 के तहत मौजा नारवा खुर्द की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है परन्तु नोटिस चस्पानगी पर दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह ज्ञात होता है कि अपीलांट की विधिवत तामिल नहीं हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय की सुनवाई के दौरान अपीलांट उपस्थित रहा हो, ऐसा अभिलेख से प्रकट नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील अपीलांट की पर्याप्त सुनवाई के अभाव में इकतरफा पारित हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार खींवसर द्वारा मौजा नारवा खुर्द के प्रकरण संख्या 11/2022 सरकार बनाम कानसिंह निर्णय दिनांक 18.05.22 अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को पुनःप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।


(राकेश कुमार गुप्ता)

अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर